यूपीआई ने बनाया मार्च में नया रिकॉर्ड

29.53 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हुआ लेनदेन

नई दिल्ली,02 अप्रैल. भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने मार्च में नया रिकॉर्ड बना दिया है. इस दौरान 22.64 अरब लेनदेन के साथ 29.53 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, यह किसी भी महीने का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. यूपीआई की तेज रफ्तार न केवल देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है, बल्कि भारत को वैश्विक फिनटेक क्षेत्र में भी मजबूत स्थिति में ला रही है. बुधवार- भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए मार्च महीने में रिकॉर्ड लेनदेन दर्ज किया है.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान 22.64 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक आंकड़ा है. लेनदेन की कुल वैल्यू भी बढ़कर 29.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पिछले महीनों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है.

फरवरी में जहां 20.39 अरब ट्रांजैक्शन हुए थे, वहीं जनवरी में यह आंकड़ा 21.70 अरब था. डेली ट्रांजैक्शन औसत भी मामूली बढ़कर 730 मिलियन तक पहुंच गया, हालांकि औसत दैनिक वैल्यू में हल्की गिरावट देखी गई. यूपीआई ऐप्स में फोनपे ने 45.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अपनी बढ़त बनाए रखी, जबकि गूगल पेय और पेटीएम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. विशेषज्ञों का मानना है कि यूपीआई का बढ़ता उपयोग और अंतरराष्ट्रीय विस्तार भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से आगे बढ़ा रहा है.

सिम बाइंडिंग नियम अब 1 जनवरी 2027 से लागू

नई दिल्ली, 02 अप्रैल. केंद्र सरकार ने 'सिम बाइंडिंग' नियमों को लागू करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है. इसका मतलब है कि ये नए नियम अब 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे. इस व्यवस्था के तहत व्हाट्सप्प, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे मैसेजिंग एप तभी काम करेंगे जब आपका रजिस्टर्ड सिम उसी मोबाइल फोन में मौजूद होगा. यदि सिम कार्ड फोन से बाहर निकाला गया तो कंप्यूटर पर लॉगिन वॉट्सएप 6 घंटे में ऑटोमैटिक लॉगआउट हो जाएगा. सिम बाइंडिंग एक सुरक्षा उपाय है, जिससे आपके मैसेजिंग एप आपके फिजिकल सिम कार्ड के साथ लॉक हो जाते हैं. इससे किसी भी हैकर या ठग के लिए आपके नंबर का गलत इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा.

30 जून तक पेट्रोकेमिकल्स पर ड्यूटी माफ

विनिर्माण बढ़ाने को सरकार ने दी बड़ी राहत

बिक्री पर सीमा शुल्क में रियायतें अनुसूचित

नई दिल्ली, 02 अप्रैल. बजट 2026-27 की घोषणा के अनुरूप विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निर्मित वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री पर सीमा शुल्क में रियायतों को कुछ शर्तों के साथ अधिसूचित किया गया है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वैश्विक व्यापार व्यवधानों से प्रभावित विनिर्माण इकाइयों की क्षमता उपयोग को बेहतर बनाने के लिए इस बार के बजट में यह छूट देने के प्रावधान किए गए हैं. शुल्क में रियायत की यह सुविधा खनिज उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, प्लास्टिक एवं रबर, चमड़ा, चमड़े के उत्पाद और फर से बने सामान, लकड़ी, कॉर्क एवं कागज, वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद, जूते एवं टोपी, पत्थर, सिरेमिक एवं कांच, धातु और उनसे बने सामान, मशीनरी एवं विद्युत उपकरण, वाहन, विमान एवं परिवहन उपकरण, ऑप्टिकल, चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उपकरण, हथियार और गोला-बारूद और विविध निर्मित वस्तुओं सहित कई क्षेत्रों को कवर करता है. मंत्रालय ने कहा कि इस उपाय से लगभग 1,200 एसईजेड विनिर्माण इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद है. इससे बड़े पैमाने का उत्पादन हो सकेगा, लागत कम होगी और विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती बढ़ेगी.

रिपोर्ट के अनुसार, तीन रियायतों की पात्र एसईजेड विनिर्माण इकाइयां रियायती शुल्क दरों पर डीटीए को माल भेज सकती हैं, बशर्ते यह सीमा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वर्ष में प्राप्त उच्चतम वार्षिक फ्री ऑन बोर्ड निर्यात मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित हो. दोहरे लाभ से बचने के लिए, इनपुट पर शुल्क छूट जैसे निर्यात लाभों की अनुमति नहीं है. इस अधिसूचना में पात्रता की प्रमुख शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनमें एसईजेड में न्यूनतम 20 प्रतिशत मूल्यवर्धन शामिल है, जिसकी गणना मूल्यांकन योग्य मूल्य और इनपुट लागतों पर आधारित एक परिभाषित सूत्र का उपयोग करके की जाती है.

कपड़ा निर्यातकों को राहत, करों में छूट की योजना छह महीने बढ़ी

नई दिल्ली, 02 अप्रैल. केंद्र सरकार ने कपड़ा निर्यातकों को राहत प्रदान करते हुए केंद्रीय तथा राज्य करों और उपकरों में छूट की अवधि छह महीने बढ़ा दी है. मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि छूट 30 सितंबर 2026 तक या सक्षम प्राधिकारी द्वारा 16वें वित्त आयोग चक्र के लिए योजना की स्वीकृति तक बढ़ा दी गयी है.

योजना के तहत अन्य सभी दिशा-निर्देश यथावत बने रहेंगे. इस योजना की शुरुआत 07 मार्च 2019 को की गयी थी. सभी परिधान तथा गैर-परिधान वस्त्र इसके दायरे में आते हैं. इसका उद्देश्य उन सभी अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों एवं उपकरों की भरपाई करना है जो किसी अन्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं ताकि देश का परिधान और अन्य वस्त्र निर्यात वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे. मंत्रालय ने बताया कि यह योजना निर्यात के शून्य-रेटिंग के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि निर्यातित उत्पादों में शामिल गैर-रिफंड योग्य कर निर्यातकों को वापस मिले. इससे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को काफी राहत मिल रही है. जो कपड़ा उत्पाद इस योजना के तहत कवर नहीं होते हैं उनके लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना को भी 1 अप्रैल से 3 सितंबर 226 तक जारी रखा गया है.

ट्रंप के बयान से सोना-चांदी में भारी गिरावट

02 प्रतिशत की गिरावट में रहा सोना

05 प्रतिशत पर लुढ़की चांदी

नई दिल्ली, 02 अप्रैल. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति के ताज़ा बयान के बाद सोना और चांदी की कीमतों में गुरुवार को तेज गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों को जहां संघर्ष-विराम की उम्मीद थी, वहीं अनिश्चितता बढ़ने से बाजार में बिकवाली हावी हो गई.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी दोनों के वायदा भाव में भारी गिरावट देखी गई. खासकर चांदी में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया. इस उतार-चढ़ाव ने बुलियन बाजार की दिशा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं. गुरुवार- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान के बाद गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के वायदा भाव में 2.31 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे कीमतें इंट्रा-डे में 1,50,145 रुपये तक पहुंच गईं. वहीं चांदी में और भी तेज गिरावट दर्ज की गई, जो 5.59 प्रतिशत टूटकर 2,29,888 रुपये के स्तर तक लुढ़क गई. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशक मध्य-पूर्व में जारी तनाव के जल्द खत्म होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के बयान ने इस उम्मीद को झटका दिया. उन्होंने जहां संघर्ष के समाप्त होने के संकेत दिए, वहीं ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी. इससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई और निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के बजाय मुनाफावसूली शुरू कर दी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसका असर दिखा, जहां हाजिर सोना और चांदी दोनों में गिरावट आई. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में भू-राजनीतिक घटनाक्रम के आधार पर बुलियन बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

एयरटेल ने 95 करोड़ से अधिक ग्राहकों का आंकड़ा छुआ

नई दिल्ली,02 अप्रैल. देश की अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने 65 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा छू लिया है.

एयरटेल ने गुरुवार को जीएसएमए के आंकड़ों के हवाले से बताया कि मोबाइल सब्सक्राइबरों के मामले में वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है जो भारत के अलावा अफ्रीकी देशों में भी सेवा प्रदान करती है. अफ्रीका के 14 देशों में उसके 17.9 करोड़ ग्राहक हैं. एयरटेल के कार्यकारी उपाध्यक्ष गोपाल विट्टल ने कहा कि वैश्विक स्तर पर 65 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा छूना कंपनी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया है ताकि वह हर दिन अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सके.

विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार निचले स्तर पर पहुंची

मुंबई, 02 अप्रैल. लागत मूल्य में तेज वृद्धि, कमजोर मांग और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनैतिक अस्थिरता के कारण मार्च में देश की विनिर्माण गतिविधियों में सुस्ती देखी गयी और विनिर्माण क्षेत्र का एचएसबीसी इंडिया खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) पौने चार साल के निचले स्तर पर आ गया.

मार्च में पीएमआई 53.9 दर्ज किया गया जो मासिक आधार पर गतिविधियों में वृद्धि तो दिखाता है लेकिन वृद्धि की रफ्तार जून 2022 के बाद सबसे कम है. फरवरी में पीएमआई 56.9 रहा था. सूचकांक का 50 से ऊपर रहना गतिविधियों में तेजी और इससे कम रहना गिरावट को दिखाता है जबकि 50 का स्तर स्थिरता बताता है. पीएमआई के आंकड़े गतिविधियों की मासिक आधार पर तुलना करते हैं. इसके आंकलन में उत्पादन के अलावा लागत, नये ऑर्डर, उत्पाद मूल्य, रोजगार सृजन आदि को भी शामिल किया जाता है.

भारत में एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हो रहा है जिससे भारतीय विनिर्माता भी प्रभावित हो रहे हैं. उत्पादन और नये ऑर्डरों में उल्लेखनीय सुस्ती दर्ज की गयी है जो मांग में कमी और बढ़ी हुई अनिश्चितता की ओर इशारा करता है.

वैश्विक संकट में भी मजबूत भारतीय कंपनियां

मुंबई, 02 अप्रैल. पहले अमेरिकी आयात शुल्क और अब पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीय कंपनियों की बैलेंसशीट मजबूत बनी हुई है और उनका कर्ज का अनुपात घट रहा है.

साख निर्धारक एजेंसी केयरएज रेटिंग्स की साख गुणवत्ता रिपोर्ट क्रेडिट रेशियो के अनुसार, साख बढ़ने और घटने का अनुपात यानी क्रेडिट रेशियो वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में कम होने के बावजूद 1 साल के औसत से ऊपर बना हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी छमाही में क्रेडिट रेशियो 1.93 रहा जबकि पहली छमाही में यह 2.56 था. इस दौरान 363 कंपनियों की रेटिंग बढ़ायी गयी जबकि 188 कंपनियों की रेटिंग घटायी गयी. इस मामले में 1 साल का औसत 1.55 है. साख घटने की दर सात प्रतिशत रही जो दस साल के औसत 1 प्रतिशत से कम है. हालांकि साख बढ़ने की दर में कमी आयी है और यह लंबी अवधि के

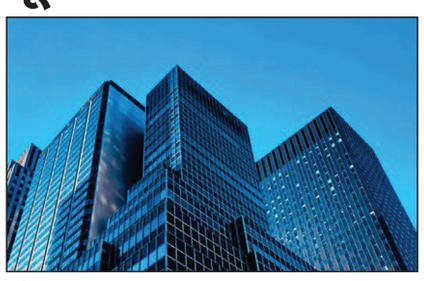

औसत 15 प्रतिशत से घटकर फिलहाल 13 प्रतिशत रह गयी है. केयरएज रेटिंग्स ने का कहना है कि इससे पता चलता है कि क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार अब कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित हो गया है. फिर भी, रेटिंग बरकरार रखने की दर 80 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है. इसका मतलब है कि बाहरी कारकों के बावजूद ज्यादातर कंपनियां अपनी स्थिति मजबूत बनाये हुए हैं.

पीपीएफ में निवेश से 25 साल में 1.03 करोड़ का फंड

नई दिल्ली, 02 अप्रैल. सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी पहले जितना ब्याज मिलता था, वही अब भी मिलेगा.

रिटायरमेंट या लंबी अवधि के लिए निवेश करने वालों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अभी भी सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प है. पीपीएफ में 15+5+5 रणनीति अपनाकर आप 25 साल में 1.03 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं. इस फंड से हर महीने लगभग 61,000 रुपए की पेंशन जैसी आय भी संभव है. पीपीएफ में 7.1 प्रतिशत का गारंटीड ब्याज मिलता है, जो कंपाउंडिंग के साथ हर साल बढ़ता है. निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी की रकम सभी टैक्स-फ्री होती है. पीपीएफ में सालाना न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है. मूल पीरियड 15 साल है, लेकिन इसे 5+5 साल के एक्सटेंशन के साथ बढ़ाया जा सकता है.

सेंसेक्स ने की शानदार वापसी

मुंबई, 02 अप्रैल.अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद गुरुवार को शुरुआती कारोबार में करीब 1,600 अंक तक टूटने वाला बीएसई का सेंसेक्स अंत में हरे निशान में बंद हुआ. सेंसेक्स 872 अंक गिरकर 72,262 अंक पर खुला और एक समय 1,588 अंक लुढ़क चुका है.

आखिरी एक घंटे में आईटी और निजी बैंकिंग कंपनियों में हुई लिवाली से यह 185.23 अंक (0.25 प्रतिशत) चढ़कर 73,319.55 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का

निफ्टी-50 सूचकांक 33.70 अंक यानी 0.15 प्रतिशत की बढ़त में 22,713.10 अंक पर पहुंच गया. श्री ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार, गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन में ईरान के खिलाफ अमेरिका के मिशन को सफल बताया, लेकिन कहा कि अगले दो-तीन सप्ताह खाड़ी देश पर हमले और तेज किये जायेंगे. इससे वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में गिरावट रही.

निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.16 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.38 प्रतिशत फिसल गया. सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में लिवाली से निफ्टी आईटी सूचकांक 2.60 प्रतिशत मजबूत हुआ. रियलटी, धातु, निजी बैंकों और एफएमसीजी में भी तेजी रही. ऑटो, फार्मा, स्वास्थ्य, मीडिया, सार्वजनिक बैंकों, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, तेल एवं गैस और रसायन सेक्टरों में गिरावट रही.

समाचार विशेष

तमिलनाडु की राजनीति में एक स्टार की एंट्री

मदुरै सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे एक्ट्रेस और भाजपा नेत्री खुशबू सुंदर के पति

चेन्नई. तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में साउथ के सुपरस्टार रहे एक्टर विजय जहां अपनी टीवीके साथ साथ मैदान में हैं तो वहीं दूसरी एनडीए ने भी स्टार कार्ड खेल दिया है. दक्षिण भारतीय फिल्मों की नामचीन अभिनेत्री खुशबू सुंदर के पति को सुंदर सी. मुदरै सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे.

खुशबू सुंदर तमिलनाडु बीजेपी की उपाध्यक्ष है. तमिलनाडु में एआईएडीएमके के अगुवाई वाली अलायंस में बीजेपी के अलावा कई दल है. खुशबू सुंदर के पति सुंदर सी को एनडीए गठबंधन के तहत पीएनके ने उम्मीदवार बनाया है. एआईएडीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल पुथिया नीधि काची (पीएनके) ने उन्हें मैदान में उतारा है.

सुंदर सी 1990 से अभिनय की दुनिया में

सक्रिय है. उनकी उम्र अभी 58 साल है. पीएनके ने जिस सीट से उन्हें मौका दिया है. उस सीट पर काफी वक्त से डीएमके का कब्जा है. 21 जनवरी, 1968 को जन्में सुंदर सी. तब सुर्खियों में आए थे. जब उनकी अभिनेत्री पत्नी खुशबू सुंदर ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे पति के प्रेशर का हवाला दिया था. दरअसल खुशबू ने डीएमके से राजनीति में कदम रखा था. तब खुद करुणानिधि ने उनका स्वागत किया था. हालांकि वह बाद में कांग्रेस में आ गई थी. कांग्रेस के बाद बीजेपी में आई थीं. बीजेपी ने उन्हें 2021 के चुनावों में चेन्नई की थाउजेंट लाइट्स विधानसभा सीट से उतारा था, लेकिन खुशबू तब 30 हजार से ज्यादा वोटों से डीएमके के सामने हार गई थी. खुशबू बीजेपी में सक्रिय हैं लेकिन इस चुनावों उनके पति राजनीति के क्षेत्र में डेब्यू करेंगे. 2021 के चुनावों में खुद खुशबू सुंदर चुनाव लड़ी थी तब उनके जीतने का सपना टूट गया था. इस बार के चुनावों में उनके पति मैदान में उतरेंगे. सुंदर सी. अभिनेता और निर्देशक हैं. वह खुशबू सुंदर के साथ विवाह बंधन में साल 2000 में बंधे थे.

डीएमके मंत्री से होगा मुकाबला

मदुरै सेंट्रल सीट पर अभी सत्ताधारी डीएमके का कब्जा है. इसका प्रतिनिधित्व सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा मंत्री पीटीआर (पलानीवेल त्यागराजन) कर रहे हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र को डीएमके का गढ़ माना जाता है. मुदरै सेंट्रल सीट पिछली बार डीएमके ने 34,176 वोटों के अंतर से जीती थी. ऐसे में सुंदर सी के सामने कड़ी चुनौती होगी कि एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर वहां से जीत दर्ज करें. वे पुथिया नीधि काची (पीएनके) पार्टी के उम्मीदवार जरूर है लेकिन वह एआईएडीएमके के सिंबल पर ही लड़ेंगे.

अंधेरे में रोशनी तलाश रहा वाम मोर्चा

लीकर चा वाली राजनीति को उबाल का इंतजार

कोलकाता. सफेद धोती-पंजाबी (कुर्ता), कंधे पर खादी का झोला, पैरों में चमड़े की चप्पल या काले रंग का पाम शू. झोले में अपने इलाके का लेखा-जोखा का खाता, प्लास्टिक की पन्नी में मूड़ी के साथ छोला (चना)-बादाम और चश्मे का डिब्बा.

बंगाल में वामपंथियों की यही पहचान रही है. उनका दिन लीकर चा(बिना दूध वाली चाय) और बेकरी के टोस्ट बिस्कुट से शुरू होता है. कोलकाता के अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित माकपा के राज्य मुख्यालय मुजफ्फर अहमद भवन की कैंटीन में एक समय सुबह से शाम तक न जाने कितनी लीटर लीकर चा बना करती थी. पार्टी के नेता चाय और टोस्ट बिस्कुट खाते हुए रणनीतियां तैयार करते थे. वैसे तो पिछले डेढ़ दशक में परिस्थितियां काफी बदल गई हैं, लेकिन 2006 के विधानसभा चुनाव में रिकार्ड 235 सीटें जीतने वाला वाम मोर्चा (वामो) अब सत्ता के गलियारे से कोसों दूर है.

वामो के सामने ढेरों चुनौतियां

वामो के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई जैसी है. उनके सामने ढेरों चुनौतियां हैं, सबसे पहली, फंड की है. वामो पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं व आम लोगों के चंदे पर चल रही है. उद्योग जगत से आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं है. उसे सीमित फंड के साथ चुनाव प्रचार करना पड़ेगा. दूसरी, इंटरनेट या अन्य मीडिया के जरिए प्रचार करने में भी काफी पीछे है. इनका आईटी सेल भी मजबूत नहीं है.

केरल में चेन्निथला बनाम केसीवी

सरकार बनने की उम्मीद में मुख्यमंत्री पद की खींचतान

तिरुवनंतपुरम. केरल में तमाम चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के अनुमान लगाए जा रहे हैं. ज्यादातर सर्वे बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार बना सकती है. तभी चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं में मुख्यमंत्री पद की खींचतान शुरू हो गई है.

पार्टी के बड़े नेता खेमों में बंटने लगे हैं. एक तरफ कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक रमेश चेन्निथला हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस के संगठन महासचिव और राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल यानी केसीवी हैं. इनके अलावा विधायक दल के नेता वीडी सतीशन भी दावेदार हैं. लेकिन चेन्निथला बनाम केसीवी के मुकाबले में वे थोड़े पिछड़ते दिख रहे हैं.

पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के सांसद के सुधाकरण ने खुल कर कहा है कि रमेश चेन्निथला को राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए. पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में उप सभापति रहे पीजे कुरियन ने भी कहा है कि चेन्निथला मुख्यमंत्री पद के सबसे उपयुक्त दावेदार हैं. कांग्रेस के कई पुराने नेताओं का यह भी कहना है कि 1 साल पहले यानी वाम मोर्चा के सरकार में आने से पहले भी जब कांग्रेस की सरकार बनी और ओमन चांडी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो रमेश चेन्निथला का हक मार कर एके एंटनी ने चांडी को सीएम बनवाया था. इसका अर्थ है कि चेन्निथला दशकों से सीएम पद के दावेदार हैं.

विशेष | चुनाव प्रचार में उतरी हेमंत सोरेन की टीम

झारखंड की राजनीति का नया रणक्षेत्र असम

रांची. असम विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड की राजनीति का फोकस तेजी से पूर्वोत्तर की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से 18 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर चुनावी मुकाबले को नई दिशा दे दी है. इसके साथ ही वे अपनी पूरी टीम के साथ असम में कैंप कर रहे हैं, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि चुनाव तक झारखंड के कई प्रमुख नेता राज्य से बाहर सक्रिय रहेंगे.

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के इस आक्रामक विस्तारवादी रुख ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं. मुख्यमंत्री लगातार सभाएं, रोड शो और रणनीतिक बैठकों के जरिए स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री की सक्रियता के जवाब में भाजपा ने भी रणनीतिक कदम उठाया है. पार्टी ने झारखंड के कई नेताओं को असम में प्रचार के लिए भेजने का फैसला किया है.

खास तौर पर उन इलाकों पर फोकस किया जा रहा है, जहां हेमंत सोरेन खुद सक्रिय हैं. भाजपा की कोशिश है कि झामुमो के प्रभाव को सीमित किया जाए और स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक मजबूती का लाभ उठाया जाए.

कांग्रेस ने भी कसी कमर, दिया टारगेट

इधर, कांग्रेस ने भी अपने मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे असम में निर्धारित सीटों पर जीत सुनिश्चित करें. पार्टी आलाकमान ने खास तौर पर यह संदेश दिया है कि जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, वे अपने प्रभाव और नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल करें. मंत्रियों ने झारखंड में अपने निर्धारित कार्यक्रम टाल दिए हैं और असम में कैंप करने की तैयारी है. कांग्रेस के भीतर इसे प्रदर्शन आधारित राजनीति के रूप में देखा जा रहा है, जहां नेताओं की सक्रियता और परिणाम दोनों पर नजर रखी जा रही है. असम चुनाव में झारखंड के नेताओं की यह व्यापक भागीदारी सिर्फ चुनावी प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत भी है. यदि झामुमो और सहयोगी दल बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो यह क्षेत्रीय दलों के विस्तार की नई संभावनाएं खोल सकता है. वहीं, भाजपा और कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है.